RAJYA SABHA

Tuesday, the 25th April, 2000/5 Vaisakha, 1922 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण

*421. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:** †
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च-शिक्षा के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से शुरू की गई है;

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान किस-किस पाठ्यक्रम के लिए कितनी-कितनी ऋण राशि प्रदान की गई; और

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान इन ऋणों को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और बड़े शहरों, छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले ऐसे छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक देश में उच्च अध्ययन हेतु छात्रों को शिक्षा ऋण देते हैं। ये ऋण अलग-अलग बैंकों की योजना के तहत और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई योजना के तहत दिए जाते हैं। विभिन्न बैंकों ने विभिन्न तारीखों से अपनी योजनाएं शुरू की थीं। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त, 1995 के आदेश के एक भाग के निदेश का अनुपालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1995 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए एक ऋण योजना परिचालित की थी, जिसमें बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि शैक्षिक वर्ष 1995-96 और उसके बाद से गैर-सरकारी/व्यावसायिक महाविद्यालयों में

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह द्वारा पूछा गया।

चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण दें। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.7.1999 के निदेशों का अनुपालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी व्यावसायिक महाविद्यालयों में छात्रों के लिए शिक्षा ऋण योजना के संबंध में दिनांक 31.7.1999 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए थे।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी जैसी सभी शाखाओं), इंजीनियरी, रासायनिक-प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, आन्तरिक सजावट सहित वास्तुशिल्प, कानून, कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) आदि में पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा ऋण दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके से पाठ्यक्रम वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं मिलता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खातों में बकाया शिक्षा ऋण राशि निम्नलिखित है:

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1996	73,961	183.30
1997	74,578	248.18
1998	81,797	328.88

Loans provided for higher education by the nationalised banks

*421. SHRI RAJ MOHINDER SINGH: †
SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether loan for higher education is provided by the nationalised banks in the country;

(b) if so, since when this scheme has been started;

(c) the details of the courses for which loans have been given alongwith the amount granted for each of these courses during 1996-97, 1997-98, 1998-99 and 1999-2000; and

(d) the number of students who received these loans during the above mentioned years and the number of such students from big cities, small towns and villages, separately?

*Original notice of the question was received in Hindi.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir. As per information furnished by Reserve Bank of India (RBI), banks provide educational loans to students pursuing higher studies in the country. The loans are extended under individual bank's scheme as well as under the scheme framed by the RBI. Diferent banks had launched their scheme from different dates. In compliance of Supreme Court directives forming part of its order dated 11th August, 1995, RBI had circulated a loan scheme to all Public Sector Banks in August 1995 with the instruction to banks to provide loans to students admitted to Medical/Dental courses in private/ professional colleges from academic year 1995-96 onwards. Further, in compliance with the directions of the Supreme Court dated 27.07.1999, detailed guidelines on educational loan scheme for students in private professional colleges were issued by RBI to all Public Sector Banks on 31.07.1999.

(c) and (d) The educational loans are provided by banks for courses in Medical and Dental (all branches such as Allopathic, Ayurvedic, Homeopathy and Unani), Engineering, Chemical Technology, Management, Architecture including Interior Decoration, Law, Computer Science and Application etc. The data reporting system of RBI does not generate the course-wise and area-wise break up of educational loans as sought in the question. The amount of educational loans outstanding in the books of Public Sector Banks during three years are as under:

Year (As on 31st March)	No. of Accounts	Amount Outstanding (Rs. In crores)
1996	73,961	183.30
1997	74,578	248.18
1998	81,797	328.88

श्री राज मोहिन्दर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के लिए जो लोन स्टूडेंट्स को देने की स्कीम इसलिए शुरू की गई थी कि हमारे यहां गांव के जो लोग हैं उनके पेरेंट्स के पास इतनी राशि नहीं होती कि वे अपनी औलाद को अच्छे कॉलेजों में पढ़ा सकें। हमारे यहां हायर एजुकेशन की दर, कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स पढ़ने

जाते हैं, अच्छे कोर्सेस के लिए वह 6 परसेंट है जबकि डेवलेपमेंट कंट्रीज में इनकी दर 20 परसेंट तक है। मेरा खयाल है कि जो जवाब दिया गया है उसमें मेडीकल, डेंटल, एलोपैथी, होम्योपैथी जैसी कोर्सेस के लिए लोन प्रोवाइड किए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर की हायर एजुकेशन के लिए भी कोई राशि दी जाती है? अगर नहीं दी जाती तो क्या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को यह राशि देने की आपकी कोई स्कीम है?

सभापति महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दूसरा क्वेश्चन आप सप्लीमेंट्री में कर लीजिएगा।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति महोदय, इनका कहना सही है। आजकल बैंक की जो ओरिजनल स्कीम हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देने के बाद शुरू हुई है, बच्चों को लोन देने की, उसमें एग्रीकल्चर और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है लेकिन इनके सुझाव पर गौर किया जा सकता है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी लोन देने में। एग्रीकल्चर और उसके जैसे किसी और प्रोफेशन के बारे में भी ये जो सुझाव देंगे हम उन्हें भी देखेंगे।

श्री राज मोहिन्दर सिंह: सभापति महोदय, सेकिंड सप्लीमेंट में मैं पूछना चाहूंगा कि जो टेरेरिस्ट अफेक्टिड स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिक राशि नहीं दे सकते तो क्या ऐसी कोई स्कीम है कि टेरेरिस्ट अफेक्टिड स्टेट के स्टूडेंट्स को लोन ज्यादा दिया जाए? अगर देते हैं तो ठीक है नहीं देते तो क्या आगे कोई स्कीम है कि टेरेरिस्ट अफेक्टेड स्टेट के स्टूडेंट्स को ज्यादा राशि दी जाए।

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, इनका कहना ठीक है कि अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि टेरेरिस्ट अफेक्टिड स्टेट के स्टुडेंट्स को ज्यादा लोन दिया जाए। सभी स्कीमें हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके लिए यूनिवर्सल हैं, यूनिफॉर्म हैं लेकिन इनके सुझाव पर हम गौर करेंगे और जहां तक हो सकेगा मदद करेंगे।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, according to the Statistical Year Book of the UNESCO, the expenditure on higher education in our country is considered as a non-merit subsidy. It had been considered by the Ministry of Finance for many years. I think this has never been brought to the notice of the present Finance Minister. I would like to remind the hon. Finance Minister that the access to higher education has been going down from the First Five Year Plan to the Ninth Five Year Plan and out of the total

expenditure of six per cent on education, only a fraction of the funds is available for higher education. I would like to know from the hon. Finance Minister whether providing soft loans to the needy students for higher education will be kept in the prirority sector.

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, अभी तक शिक्षा के लिए जो लोन है वह प्रायोरिटी सैक्टर में है और प्रायोरिटी सैक्टर ही उनको लोन दे रहा है। ऋण पर ब्याज की जो दर है वह अभी 12 परसेंट है। लेकिन अभी सभी बैंकों ने और रिजर्व बैंक ने ऋण पर ब्याज की दर में कटौती की है इसलिए उसका लाभ भी उनको देने की कोशिश करेंगे।

दूसरा सवाल साफ्ट लोन फॉर दी नीडी स्टूडेंट्स का है। जहां तक बिलो पावर्टी लाइन का सवाल है उसके बारे में माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर हम सोचेंगे क्योंकि उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। है।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, in view of the steep rise in the fees being charged in higher educational institutions, it is essential that our banks should provide loans to deserving students. When our Government was in office we had also instituted a scheme for providing income-tax concessions for loans taken by such students. I would like to know from the hon. Minister what the present state of affairs is with regard to income-tax concessions for loans being given to such students.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, the hon. Leader of the Opposition would recall that in the Budget which I presented to the Parliament on the 29th of February this year, I have raised the exemption limit in income-tax for loans, which the student get for technical and professional courses, from Rs. 25,000 to Rs. 40,000. That has already been done.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, most of us agree that a major part of the resources allocated for education should go for primary education, basic education and middle-level education. But higher education is also important. The real issue, in my view, is improving the quality of both primary and middle-level education and higher education. This has already been mentioned that only six per cent of the people from the relevant age group is going for higher education. They cannot afford it. The UGC has asked the universities to generate their own resources. The universities find it difficult to generate their own resources. We must see to it that higher education does not

become an exclusive preserve of the affluent students only. In this context, I have a question to put. Part (a) of my question is: What are the terms of the loans to the needy students, not only for those who are below the poverty line but also for those who are deserving? In the UNCTAD the Indian Declaration has been included, but not biotechnology. What about the other areas and what are the terms of the loans? Part (b) of my question is: In this context, is the Government of India considering framing of a national policy for providing soft loans to students to enable them to pursue higher studies?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, अभी तक बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं, उन्हें ही लोन देने की सुविधा है और जिनके मां-बाप की कुल आय एक लाख रुपये से ज्यादा है, उनके बच्चों को यह लोन नहीं दिया जाता, एक लाख से कम आय वाले मां-बाप के बच्चों को यह लोन दिया जाता है। इसमें यह प्रावधान है कि जो सरकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज हैं, उसमें 50 हजार रुपया उनको ऋण दिया जाता है। वह क्लीन लोन है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को देते हैं, बाकी बच्चों को ऋण नहीं देते हैं। दूसरा जहां तक सॉफ्ट लोनस् का सवाल है, उसका जवाब मैंने पहले दे दिया है।

PROF (SHRIMATI) BHARATI RAY: But what about the National Policy? I would like to know whether you are trying to formulate a national policy in this regard.

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सभापति जी, वैसे तो जो फ्री सीट प्राइवेट कॉलेज में हैं और जो पेमेंट सीट हैं, उसको देते हैं, एन०आर०आई० को नहीं देते हैं। सभी कॉलेजों के लिए सरकार की राष्ट्रीय नीति है। हम यह भी सोच रहे हैं कि जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें भी उनका बंटवारा हो जाए और जो प्रोफैशनल ऐजूकेशन हमारी लिस्ट में नहीं है, उसमें सभी के अंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, प्रश्न के "घ" भाग में लिखा है "उपर्युक्त वर्षों के दौरान इन ऋणों को प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और बड़े शहरों, छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले ऐसे छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है?" इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। कितनी राशि उपलब्ध की गयी, इसके दो आंकड़े दिये हैं। सर, सामाजिक, शैक्षणिक विभाग में कई वर्षों से एक असमानता, विषमता बनी हुई है। मेरा सवाल है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, इस क्षेत्र में से कितने छात्रों को कितनी मात्रा में यह रकम अदा की गयी? मंत्री जी कृपया आदिवासीयों की, दलितों की संख्या बताएं और कितनी रकम का प्रावधान किया गया, वह भी बताएं?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: सर, अभी हमने क्लासीफिकेशन नहीं किया है। हम इस बारे

में चिंतित हैं। क्लासीफिकेशन होना जरूरी है और छात्रों की संख्या भी जरूरी है। लेकिन जो अकाउंट्स का नम्बर होता है, वह छात्रों की संख्या हो जाती है। It is 81,000 because number of accounts is related with the number of students. जो क्लासीफिकेशन शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स और ओ॰बी॰सी॰ का है, वह इनफारमेशन अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

SHRI SWARAJ KAUSHAL: Sir, the figures are quite impressive. May I know from the hon. Minister as to what rate of interest is charged on this loan amount? Secondly, what is the security which you ask for, to extend this loan facility?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: As of today, upto Rs. 50,000/- we do not ask for any security. But beyond Rs. 50,000, as per the conditions of the parents, banks do request for collateral security, may be an LIC Policy which they have or some other things.

SHRI SWARAJ KAUSHAL: What is the rate of interest?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: As of today, the rate of interest is 12% But, as I said earlier in this august House, we can reduce the interest rate because the total environment is such that there is reduction in the interest rates and the RBI has also announced reduction in the interest rates. So, the rate of interest will be according to that.

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU: According to Shri Amartya Sen, a Nobel prize winner and a great economist, the returns from higher education in India have been low. Therefore, the Government must spend more on basic education. He has also pointed out that since higher education has not produced good results, why should we spend on it? Amartya Sen's call amounts to abandonment of our higher education policy. Whether the Government is aware of Shri Amartya Sen's statement? I so, what is its reaction?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the hon. Member has raised a larger issue. In fact, I find that number of Members have raised larger issues in regard to the expenditure of the Government on higher education, the support that the banks and financial institutions might give to higher education. It is a fact that we are spending less than what we should be spending on higher education and on education in general. That is a fact of life. But we are spending less on a number of things because everyone is short of resources, including the Government of India. When it comes to allocation of resources to compeling claims, we try and balance it out as well as one can. But as far as the limited

question of support of banking institutions to higher education is concerned, I think my colleague has explained in detail the various schemes which are in existence. He has also assured the House, through you, that there are some issues which remain outstanding and already we have taken a view that we will be discussing this matter with the RBI and doing whatever we can to facilitate the flow of banking funds by way of loans to more and more meritorious students, students belonging to the SC and the ST categories, students belonging to poor families so that absolutely nobody is deprived of higher education in this country on account of lack of funds irrespective of whatever family background he comes from. That is the general approach of the Government.

White Paper on Amendments to the Constitution of India

*422 SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are thinking to issue a White Paper on amendments to the Constitution of India; and

(b) if so, whether Government are aware of recent Press Reports of a meeting of four former Prime Ministers Objecting to the move to review the Constitution by passing the Parliament?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): (a) No, Sir.

(b) The objections raised by four former Prime Ministers regarding the setting up of the National Commission to Review the Working of the Constitution have appeared in the "Hindustan Times" dated March 3, 2000.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Mr. Chairman, Sir, my first question is this. Has the Government taken note of the objections of the former Prime Ministers because the Commission has already been appointed? Secondly, the spokesman of the Government told the Press that they are thinking of issuing a White Paper about the amendments which have already been made. What has happened to the announcment of the spokeman?

SHRI RAM JETHMALANI: Mr. Chairman, Sir, I don't believe that the Government has made any announcement that a White Paper is going to be issued. We have taken due note of the criticism levelled by the four venerable gentlemen. But that has not changed the course of the Government and very rightly.